साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 05 जुलाई 2021, वर्ष-7, अंक-14

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

सहकारिता आंदोलन से ही होगा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

मुख्यमंत्री ने किया 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 का शिलान्यास

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवसः सहकारिता से बेहतर पुनर्निर्माण पर मुख्यमंत्री ने कहा

सहकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व उद्देश्य की स्पष्टता को बनाए रखना जरूरी

सहकारिता से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनिधि करें नवाचार और रचें इतिहास

संवाददाता, भोपाल

सहाकरिता में अपार संभावनाएं है। मैं के स्थान पर हम का भाव ही सहकारिता है। सब मिलकर काम करें और सबके भले में अपना भला का भाव सहकारिता ही है। कोरोना संक्रमण की चुनौती का प्रबंधन हो या लोगों के रोजगार और व्यापार को स्थापित करना हो, सहकारिता का सिद्धांत उद्धार का रास्ता दिखाता है। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समन्वय भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण समारोह के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने विपणन सहकारी संघ तथा आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण तथा 114 गोदामों का शिलान्यास डिजिटली किया। इन कार्यों की लागत लगभग 77 करोड़ 75 लाख रुपए है। इस अवसर पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता अजीत केसरी भी उपस्थित थे। सीएम ने कोल्ड स्टोरेज राऊ इंदौर, सीहोर, विदिशा और पैक्स बोरक्षार अलीराजपुर के सदस्यों से ऑनलाइन संवाद भी किया।

मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया बोले

सहकारिता में नवाचार जरूरी

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारिता हमारे देश और समाज की रग-रग मे बसी है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। उद्यानिकी, खनिज, श्रम और सहकारिता क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। अब सहकारी संस्थाओं का ऑन लाइन पंजीयन 45 दिन के अंदर हो रहा है। सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत होने वालों प्रकरणों की भी ऑन लाइन प्रक्रिया से सुनवाई की जा रही है। सहकारी आंदोलन से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। सहकारिता में लोगों को जोड़ने और दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कोरोना काल की विपदा में सहकारिता बेहतर पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। परिवहन, मत्स्य उत्पादन, गृह निर्माण, ग्रामीण पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर गतिविधियों के संचालन से रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। सहकारिता के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का गलत उपयोग न हो। निरंतर मॉनिटरिंग और सतर्कता आवश्यक है। सहाकरिता के सिद्धांत पर गठित गृह निर्माण समितियों में प्लाट हड़पने के कई प्रकरण सामने आएं हैं।

मप्र का पुराना इतिहास

मध्यप्रदेश में सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। जबलपुर के सीहोरा में 1904 में सहकारी बैंक स्थापित हुआ। प्राथमिक सहकारी समितियां खाद और बीच के लिए किसानों का सबसे बड़ा सहारा है। किसानों को शून्य-प्रतिशत पर कर्ज की सुविधा से बहुत राहत मिली है।

सांची ने बनाई पहचान

सहकारिता में आज अमूल जैसा संगठन पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। मप्र के सांची ब्रांड ने भी अपनी पहचान बनाई है। संतरों के लिए मालवा फ्रैश ब्रांड के साथ नीमच के लहसुन, बुरहानपुर के केले, अमरकंटक की गुल बकावली, डिंडोरी की कोदो-कुटकी सहित प्रदेश की वनोपज और जड़ी-बूटियों में कई संभावनाएं हैं।

पांच हॉर्स पावर का सोलर पंप लगाने पर 30 प्रतिशत छूट

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में पांच हार्स पावर का सोलर पंप लगाने वाले किसानों को अब बिजली से चलने वाले उसी क्षमता के पंप पर मिलने वाली सब्सिडी में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत जहां बिजली है, वहां सोलर पंप को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे किसानों को सोलर पंप लगाने पर 30 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। इससे अधिक क्षमता के बिजली से चलने वाले पंपों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की जाएगी।

दरअसल, सिंचाई में सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत सरकार किसानों को अनुदान उपलब्ध कराएगी। यह केंद्र सरकार के बराबर 30 फीसद होगा। किसान का अंशदान नए प्रावधान लागू होने पर बढ़ जाएगा पर जो करीब 50 हजार आवेदन लंबित हैं, उनमें किसानों को पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही अनुदान मिलेगा। यह निर्णय हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ी
- सोलर पंप पर अनुदान लेने वाले किसानों को बिजली बिल पर न मिले लाभ
- मंत्री नरोतम, पटेल, यशोधरा, भदौरिया सहित अन्य मंत्रियों ने दिए सुझाव
- 50 हजार लंबित आवेदनों का निपटारा योजना के पुराने प्रावधान पर होगा
- सोलर पंप योजना को मंजूर, जहां बिजली नहीं वहां तत्काल होगी लागू

एक किसान को एक योजना में मिले अनुदान : सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने एक किसान को एक ही योजना में अनुदान देने की बात रखी। दरअसल, कृषि विभाग किसानों को बिजली बिल में अनुदान देता है ताकि सस्ती बिजली मिले। दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें सालाना खर्च किए जाते हैं। वहीं, सोलर पंप योजना में भी अनुदान दिया जाता है। इसका लाभ छोटे किसानों की तुलना में बड़े किसान अधिक उठाते हैं।

सीएम ने जताई सहमति

कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सोलर पंप योजना में जिन्हें अनुदान का लाभ दिया जाए, उन्हें अन्य योजना में बिजली बिल पर अनुदान न दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर सहमति जताई कि ऐसे किसानों को दो-दो अनुदान का लाभ नहीं लेना चाहिए। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में अनुदान को नए सिरे से तय करने का प्रस्ताव रखा।

इनका कहना है

मेरा सुझाव है कि सरकार एक बार में सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दे दे और फिर इसे खत्म कर दे। एक बार सोलर पंप लग गया तो फिर बिजली बिल ही नहीं आएगा और सरकार को बिजली अनुदान भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले दूरस्थ इलाके के किसान को योजना में शामिल किया जाए।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से राज्य का अनुदान 30 प्रतिशत रखने को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रवक्ता, मप्र शासन

किसानों और उद्योगपतियों को सौगात...

अब फूल मुरझाए तो भी मिलेगा पैसा

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने फूल की खेती करने वाले किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। प्रदेश में फूलों की खेती भी फसल बीमा योजना के दायरे में आएगी। अब तक इस खेती को योजना से बाहर रखा गया था। सरकार के फैसले से फूल की खेती करने वाले 50 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इन्हें प्रधानमंत्री आपदा योजना का लाभ मिल सकेगा। अब तक बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदा के चलते फूलों की खेती नष्ट होने पर किसानों को किसी भी तरह की राहत राशि नहीं दी जाती थी, जिससे फसल नष्ट होने पर किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होता था।

एमपी में फूलों की खेती का भी होगा फसल बीमा

फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकारी अनुदान

सरकार ने किसानों के साथ उद्यमियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। मप्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर राज्य सरकार न केवल शासकीय अनुदान देगी, बल्कि गोदाम, कच्चा माल और बाजार भी उपलब्ध कराएगी। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में लगने वाले फूड प्रोसेसिंग यूनिट से हजारों युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा था कि वह फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बड़ी संख्या में फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए उद्योगपति आकर्षित होंगे।

औबेदुल्लागंज में पहली बार होगी कोदो की खेती

50 किसानों ने 75 एकड़ में की कोदो की बोवनी आदिवासियों ने पारंपरिक खेती में दिखाई रुचि

संवाददाता, रायसेन

काले चावल के शौकीन पूरे देश में बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि विलुप्त प्राय होती इस कोदो (काला चावल) की खेती की और आदिवासियों का रुझान वापस लौट रहा है। मुख्तः इस प्रजाति की खेती आदिवासी ही करते आए हैं और इस बार भी क्षेत्र में आदिवासियों ने ही एक बार फिर से इस कोदो की खेती कर इसे जीवित रखने का बीड़ा उठाया है। औबेदुल्लागंज विखं में पहली बार लुलका ग्राम की जैविक किसान मित्रों के साथ 50 किसानों द्वारा 70 से 75 एकड़ में जेके 137 वैरायटी का कोदो बोया गया है। इस किस्म की फसल उत्पादन कर आदिवासी आर्थिक रूप से संपन्न तो होंगे ही जरूरतमंदों को भी पौष्टिकता से भरा यह अनाज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

डिंडोरी में खरीदा बीज

ब्लॉक के किसान इस बार लुलका गांव के आदिवासी किसानों ने अपनी पारंपरिक खेती कोदो में दिलचस्पी दिखाई है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा 70-75 एकड़ में 50 किसानों के यहां कोदो की बोवनी की गई है। कोदो का बीज आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिलने से उसे समिति द्वारा डिंडोरी बीज निगम क्षेत्र से तीन क्विंटल प्रमाणित बीज खरीदा गया एवं उसको 50 किसानों से बोवनी करवाई गई।

जैविक दवा भी की तैयार : जेके 137 किस्म का यह बीज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से बोया गया है। महिला स्व सहायता समूह के यहां पूर्व से कृषि विभाग द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं जहां समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक कीटनाशक दवाई भी तैयार की जा रही है।

मधुमेह के लिए फायदेमंद : कोदो मधुमेह के रोगियों के लिए बड़ा लाभकारी माना जाता है। यह काला चावल फायटोकेमिकल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है।मोटापा कम करने में भी मददगार है।

कीटनाशकों से मुक्त कोदो : कोदो भारत का एक प्राचीन अन्न है। जिसे ऋषि अन्न माना जाता था। इसके दाने में 8.3 प्रतिशत प्रोटीन, 1.4 प्रतिशत वसा तथा 65.9 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। यह रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रभावों से भी मुक्त है।

इनका कहना है

धान और कोदो के भाव में भारी अंतर है। धान का भाव जहां 2800 से -तीन हजार प्रति क्विंटल है। वहीं कोदो का रेट 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह जहां धान की पैदावार 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक है। वहीं कोदो का उत्पादन 20 से 25 है।

डीएस भदौरिया,
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

फायदेमंद, लेकिन वैज्ञानिकों के पास रिसर्च नहीं

काले गेहूं-चावल के बढ़े शौकीन

किसानों ने शुरू की ऑनलाइन बिक्री

ग्वालियर जिले के 15 से ज्यादा गांवों में हो रही खेती

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मांग

संवाददाता, ग्वालियर

काले गेहूं और चावल के शौकीन मप्र के साथ ही पूरे देश में बढ़ रहे हैं। इसी कारण किसानों ने इनकी पैदावार बढ़ाकर ऑनलाइन बिक्री चालू कर दी है। चूंकि काला गेहूं व चावल बीमारी से बचाव करते हैं, इसलिए अधिकतर किसान इनकी जैविक खेती कर रहे हैं। उक्त चावल और गेहूं शुगर रोगी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इसे मल्टीग्रेन में मिलाकर बने आटे की रोटी के रूप में भी खा रहे हैं। ग्वालियर जिले के देवरा निवासी बृजेंद्र रावत ने कहा वर्ष 2014 से कालागेहूं व चावल की छह बीघा में फसल ले रहे हैं। पहले बिक्री स्थानीय स्तर पर करते थे पर अब वे ऑनलाइन डिमांड लेते हैं। इसकी सर्वाधिक मांग उप्र, बिहार, दिल्ली छत्तीसगढ़ में है। इन दिनों बिलौआ, टेकनपुर, भगेह, घरसौंदी, मेहगांव, पुरानी छावनी, कुलैथ आदि में कई किसान काला गेहूं और चावल पैदा कर रहे हैं। बिलौआ के ही विजेंद्र सिंह चौरसिया ने कहा कि काला गेहूं-चावल में स्टार्च की मात्र संतुलित होती है।

इनका कहना है

काले गेहूं में एंथ्रोसाइनीन और फाइबर काफी होता है। यह नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक है। इसके सेवन से हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, वीपी मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द, एनीमिया जैसे रोग के नियंत्रण में काफी मदद मिलती है। चीनी की मात्रा न होने से यह शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। काला चावल फायटो केमिकल कोलेस्ट्राल के स्तर को नियंत्रित करता है। मोटापा कम करने में भी मददगार है।

-डॉ. नेहा प्रसाद,
आहार विशेषज्ञ

काले गेहूं और चावल का रकबा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस बार करीब 50 बीघा क्षेत्र में किसानों ने उक्त दोनों फसल की हैं। अब शहर के बड़े स्टोर में भी काले गेहूं व चावल के पैकेट बिक्री के लिए उपलब्ध होने लगे हैं।

-डॉ. आनंद बड़ोनिया,
उप संचालक, कृषि विभाग

काले गेहूं में सामान्य गेहूं की तरह पोषक तत्व होते हैं। इनको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक ऐसी कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है जिसमें यह साबित होता हो कि काला गेहूं शरीर के लिए बहुत फायदे मंद है या किसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है।

-प्रोफेसर एसके रॉव,
कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय

मंडी बोर्ड की बैठक में प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने योजना के बारे में विस्तार से उपस्थित व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों को कराया अवगत

जिंसों की किस्मों की मेपिंग करने वाला पहला राज्य होगा मप्र

संवाददाता, भोपाल

मंडी बोर्ड भोपाल के सभागार में प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड प्रियंका दास की उपस्थिति में मंडियों में आने वाली कृषि उपजों की प्रमुख किस्मों को चिन्हांकित किए जाने के सबंध में मप्र के मंडी समितियों में कार्य करने वाले व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार सहमति व्यापारी संगठनों द्वारा दी गई। ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज हाने वाले भुगतान पत्रक जिसमें जिंस के साथ-साथ किस्मों को दर्ज करने की सहमति व्यापारी संगठनों द्वारा दी गई। व्यापारी संगठनों की ओर से कहा गया कि ई-अनुज्ञा साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन होने तथा प्रारंभिक रूप से मुख्य फसलों यथा गेहूं, चना एवं धान की विशिष्ट किस्म एवं सामान्य किस्मों जैसे गेहूं में गेहूं एवं शरबती चने में चना एवं डालर चना, धान में धान एवं बासमती को दर्ज करने पर सहमति व्यक्त की गई। अनुज्ञा पत्र पूर्व की रीति अनुसार ही जारी होते रहेंगे। प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा उक्त योजना के बारे में विस्तार से उपस्थित व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों को अवगत कराया।

यह रहे मौजूद

बैठक में गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष, सकल अनाज व्यापारी महासंघ मध्यप्रदेश संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ मनोज काला, पूर्व मंडी बोर्ड सदस्य, इंदौर शरद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, महासंघ, हरीश ज्ञानचंदानी, अध्यक्ष, ग्रेनमर्चेट एसोसिएशन, भोपाल समीर भार्गव, अध्यक्ष, थोक अनाज तिलहन महासंघ, सिरोंज विदिशा निमेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, अनाज तिलहन व्यापारी संघ, उज्जैन, शैलेन्द्र सिंह बुन्देला, उज्जैन, चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, भोपाल साथ ही मंडी बोर्ड के अधिकारी सुनील सक्सेना अपर संचालक, आरपी. चक्रवर्ती, संयुक्त संचालक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

जंगली जानवरों से फसल बचाने खेतों की तार फेंसिंग कराएगी सरकार

मप्र होगा पहला राज्य: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अंतिम सहमति का इंतजार

खेतों में लगी उद्यानिकी फसल (सब्जी-फल) मवेशियों और वन्यप्राणियों (नीलगाय, हिरण, सांभर, चीतल) से बचाने के लिए राज्य सरकार खेतों की तार फेंसिंग कराएगी। उद्यानिकी विभाग ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का खाका खींच लिया है। अब इंतजार है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अंतिम सहमति का।

संवाददाता, भोपाल

योजना को मंजूरी के लिए शिवराज कैबिनेट में रखा जाएगा। चेन फेंसिंग के बाद किसान अपनी जमीन पर दो से तीन फसल ले सकेंगे। इसके बाद योजना मॉडल विकास खंडों में प्रयोग के तौर पर शुरू कर दी जाएगी। योजना के तहत बारहमासी फसल लेने वाले किसानों को विभाग तार फेंसिंग के लिए अनुदान देगा।

यह देश में पहला प्रयोग होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर करीब पांच लाख किसान उद्यानिकी फसलों की बोवनी करते हैं, पर बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं। करीब 15 लाख हेक्टेयर में गाय-भैंस, बकरी, वन्यप्राणी हिरण, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर फसल को तहस-नहस कर देते हैं।

20 विकासखंडों का चयन

जंगली जानवरों से फसल को बचाने में किसान के पूरे परिवार को लगना पड़ता है। इस तरह उसे दो तरफा नुकसान होता है। इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत यह योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 20 विकासखंडों का मॉडल के रूप में चयन किया है। इन्हीं से योजना की शुरुआत की जाएगी।

जानवरों से प्रभावित जिले

प्रदेश के मालवा-निमाड़, बुंदेलखंड, ग्वालियर-चंबल में नीलगाय और जंगली सुअर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनका आतंक छतरपुर, रीवा, पन्ना, मंदसौर, नीमच, रतलाम में ज्यादा है। वहीं रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल जिलों में भी फसलों का काफी नुकसान होता है।

प्रदेश सरकार 20 मॉडल विकास खंडों में करेगी इस तरह का प्रयोग

-शिवराज कैबिनेट की लगेगी मुहर: एमपी में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना

-योजना का फायदा सबसे पहले उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा

-बारहमासी खेत लेने वाले किसानों को एक हेक्टेयर से छोटे खेत के लिए 70 फीसद अनुदान

कितनी सब्सिडी

उद्यानिकी विभाग ने चेन फेंसिंग का फायदा देने के लिए चार कैटेगरी में सबसिडी का प्रस्ताव तैयार किया है। एक से 2 हेक्टेयर पर 70 प्रतिशत, 2 से 3 हेक्टेयर तक 60 प्रतिशत, 3 से 5 हेक्टेयर तक 50 फीसदी और 5 हेक्टेयर से ऊपर किसानों को चेन फेंसिंग पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

उत्पादन बढ़ेगा

किसान मवेशियों-वन्यप्राणियों से फसल बचा पाते हैं, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और आमदनी भी। इतना ही नहीं, परिवार के कुछ लोग दूसरे काम भी कर पाएंगे। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति संभलेगी।

इनका कहना है

मुख्यमंत्री की इच्छा किसानों का सहयोग करने की है। इसलिए किसानों को उद्यानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लाई जा रही है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद योजना लागू करेंगे। इससे किसान अपनी जमीन पर दो की जगह तीन बार फसल ले सकेंगे।

- भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यानिकी, मध्य प्रदेश

अगस्त से लागू होगी नई नंबर प्रणाली: अगस्त से बदल जाएंगे प्रदेश के सभी खसरों के नंबर

'क ख ग' का अब खसरों में नहीं होगा उपयोग

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में वर्तमान में जमीनों के जो खसरा नंबर लिखे जाते हैं वे अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, अर्थात इनमें नंबर के साथ क, ख, ग आदि अक्षरों का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब भू-अभिलेख पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं ऐसे में अल्फा न्यूमेरिक नंबर वाले खसरों की लिंक कम्प्यूटर नक्शे से स्थापित नहीं हो पाता है। जिससे संबंधित खसरे के नक्शे कम्प्यूटर में नहीं दिख पाते हैं।

इसे लेकर अब भू-अभिलेख विभाग अब पूरे प्रदेश में खसरा नंबर की अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली को बंद करते हुए सिर्फ न्यूमेरिक प्रणाली में करने जा रहा है। इस सबंध में सभी जिलों को आयुक्त भू अभिलेख ने खसरा नंबर सुधार के निर्देश दे दिए हैं।

landrecords.mp.gov.in/newweb/tabs/report_khasra_nowise.aspx

Print

फार्म पी-II

खसरा

NIC-CLRMP

ग्राम	अकबरपुर खालसा	हल्का	जलालपुर	रा.नि.म.	बहोड़ापुर	तहसील	ग्वालियर	जिला	ग्वालियर	वर्ष	2014- 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sample Khasra (खसरा)

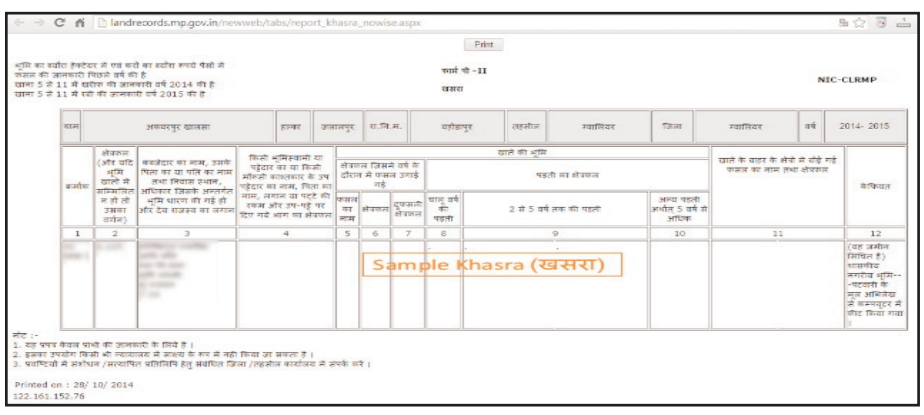

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल पक्षी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन /सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला /तहसील कार्यालय में सम्पर्क करें।

Printed on : 28/ 10/ 2014
122.161.152.76

न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा सुधार

खसरा नंबर में सुधार भू-अभिलेख सुधार की श्रेणी में आता है। लिहाजा यह सुधार मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अंतर्गत ही किया जा सकता है। जिसके लिए भू-लेख पोर्टल में तय प्रक्रिया के तहत मामला अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में जाएगा। यहां से निर्णय के बाद ही पोर्टल में नया खसरा दिखेगा। इस प्रक्रिया के बाद जिले भर के सभी खसरा नंबर अल्फा न्यूमेरिक विहीन हो जाएंगे। इसके बाद लोगों की जमीनों का नया खसरा नंबर हो जाएगा।

इस तरह होगा बदलाव

सर्वेक्षण संख्या सुधार माड्यूल के तहत पटवारी सभी खसरा नंबरों में सुधार करने के बाद पोर्टल की तय प्रक्रिया के तहत स्व-सत्यापन करेगा। फिर उसे एसडीएम को अग्रेसित करेगा। यहां आरसीएमएस में धारा 115 के तहत प्रकरण मद अ-6 में दर्ज होगा। राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया पालन के बाद एसडीएम आदेश जारी करेंगे। इसके बाद पटवारी द्वारा पोर्टल पर नया खसरा नंबर दिया जाएगा जो सिर्फ न्यूमेरिक होगा। अर्थात नए खसरा नंबरों से क, ख, ग आदि अक्षर गायब रहेंगे।

इनका कहना है

ग्राम के नक्शों में केवल आंकिक संख्या ही प्रदर्शित हो सकती है और यह संख्या ग्राम के खसरा अभिलेख में उल्लेखित खसरा नंबर से जुड़ी रहती है। लेकिन अगर कोई खसरा नंबर अल्फा न्युमेरिक है अर्थात खसरा नंबर में मिन, जुझ, क, ख, ग, घ आदि अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है तो कम्प्यूटर इस प्रकार के खसरा नंबर के साथ नक्शे की लिंक स्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए अब इन अल्फा न्युमेरिक खसरा नंबरों को अभियान के तहत सुधारा जाए। इसके लिए भू-लेख पोर्टल पर सुविधा दे दी गई है।

– ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयुक्त भू-अभिलेख

मप्र में साकार होता सहकारिता का सपना

डॉ. आनंद प्रकाश शुक्ल
वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल

वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब देश और दुनिया जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे दौर में भी मप्र जनसहभागिता का एक आदर्श माडल प्रस्तुत करके देश और दुनिया में चर्चा में बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में मप्र सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट के अलावा जनसहभागिता का जो सहारा लिया है वह वास्तव में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने जैसी गंभीर चुनौती के बीच मप्र ने बीते दो वर्षों में रवी और खरीफ का रिकार्ड उपार्जन कर देश के अन्य राज्यों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है।

मानव जीवन में सहयोग और सहकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनादिकाल से विभिन्न स्वरूपों में इसका महत्व देखने को मिलता है। विकास की अवधारणा को सहकारिता की बुनियाद पर ही खड़ा किया जाता है। यह सही है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित सरकारें आम आदमी के लिए जब सहकार बन जाए तो समाज निश्चित ही आत्मनिर्भर और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ जाता है। मप्र की शिवराज सरकार सहकार की मूल भावना के अनुरूप निर्णय लेकर प्रदेश के आम जनमानस को बेहतर जीवन जीने का आधार खड़ा करती आ रही है। खास बात यह है कि सीएम शिवराज के इस सपने को जमीन पर उतारकर साकार करने में विभाग के मंत्री अरविंद भदौरिया दिन रात एक किए हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब देश और दुनिया जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे दौर में भी मप्र जनसहभागिता का एक आदर्श माडल प्रस्तुत करके देश और दुनिया में चर्चा में बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में मप्र सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट के अलावा जनसहभागिता का जो सहारा लिया है वह वास्तव में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने जैसी गंभीर चुनौती के बीच मप्र ने बीते दो वर्षों में रवी और खरीफ का रिकार्ड उपार्जन कर देश के अन्य राज्यों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश में 15 माह की पूर्ववर्ती सरकार की यदि बात छोड़ दी जाए तो 129 लाख मौट्रिक टन रिकार्ड गेहूं का उपार्जन कर मप्र ने इतिहास रचने का काम किया है। सबसे अहम बात यह है कि संपूर्ण उपार्जन सुरक्षित तरीके से किया गया। इस उपार्जन के तत्काल बाद किसानों के खातों में 25 हजार करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने का काम भी राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में किया है। वर्ष 2021-22 का गेहूं का उपार्जन भी अब रिकॉर्ड बनाने के करीब है। इसके साथ ही बीते एकबर्ष में राज्य की शिवराज सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख नल कनेक्शन देने का काम किया है। 6 दशकों से इसका इंतजार था। इसके साथ ही बुदेलखंड के 9 ब्लाकों में जल संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार के सहयोग से महत्वाकांक्षी योजना भी शरुरू हो गई है। आने वाले दिनों में पेयजल संकट को दूर करने के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों को भी पानी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। राज्य सरकार की सहकार भावना का सबसे सशक्त कदम इस रूप में भी दिखाई देता है कि निर्धन परिवारों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने के मामले में वायोमैट्रिक पद्धति लागू करने में मप्र देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। एक देश, एक राशन कार्ड योजना को लागू करने में मप्र की भूमिका अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। इसका परिणाम है मप्र के नागरिकों को देश के कई राज्यों में नि:शुल्क राशन मिलना सुनिश्चित हो गया है। वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 3 माह का नि:शुल्क राशन निर्धन परिवारों को देने का काम कोरोना काल में किया गया है। मप्र में 4.82 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। आंकड़े बताते हैं कि 4.35 लाख नए लाभार्थी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत आधार स्तंभों पर खड़ी है। प्रदेश में लगातार सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो रही है और अन्नदाता को समय पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। जिसके चलते खेती को लाभ का धंधा बनाने की ओर प्रदेश सरकार तेजी से अग्रसर है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को शून्य प्रतिशत व्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। सीएम शिवराज सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में विपणन सहकारी संघ एवं आवास निर्मित 55 गोदामों का लोकार्पण एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा नवीन स्वीकृत 114 गोदामों का शिलान्यास भी आनलाइन किया। सरकार की मंशा स्थानीय स्तर पर उपार्जित होने वाली कृषि फसलें, फल, सब्जी, फूल, मशाले, दूध आदि का समय पर उपार्जन, उनकी कीमतों का भुगतान, उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक और बेहतर कदम उठाते हुए सहकारी संघ में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है लोक प्रबंधन या कृषि आधारित फसलों के लिए जिस प्रकार का माइक्रो मैनेजमेंट अब प्रदेश में दिख रहा है, अब वह दिन दूर नहीं, जब मप्र का किसान आत्मनिर्भर होगा। कुल मिलाकर प्रदेश के मुखिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कही गई यह बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि मिलकर जिएंगे यह सहकारिता का भाव है।

ऑफ दि ट्रैक: 'लॉन्ग कोविड' की अनदेखी

मृत्युंजय राय

कोरोना वायरस की पहली लहर जब देश में आई, तब कुछ साइंस मैगजीन ने साइंटिस्टों और डॉक्टरों के हवाले से 'लॉन्ग कोविड' के खतरों को लेकर सावधान किया था। 'लॉन्ग कोविड' का मतलब यह है कि शरीर में संक्रमण खत्म होने के कुछ महीनों बाद तक थकान और नींद न आने जैसे लक्षणों का बने रहना, लेकिन तब बहुत कम लोगों ने इन खबरों पर ध्यान दिया। इस साल वायरस की दूसरी लहर आई।

इस दौरान बीमार पड़े कई लोगों में संक्रमण दो-तीन महीने पहले खत्म हो चुका है, लेकिन वे थकान और नींद न आने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, कोविड वायरस से संक्रमित हर 10 में से एक व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। कुछ दूसरे वायरसों से संक्रमित होने पर भी ऐसी समस्याएं सामने आती रही हैं। सार्स भी कोरोना वायरस है। इसके संक्रमण से बचे 30 फीसदी लोगों में चार साल बाद भी भारी थकान की समस्या का पता चला था। साइंटिस्ट और डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड-19 वायरस से बड़े पैमाने पर लोग इस तरह के मर्ज का शिकार होने जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि अभी तक सरकारों और चिकित्सा तंत्र का इस ओर बहुत ध्यान नहीं गया है। ना ही इसे लेकर सरकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को इस बारे में बताया जाना चाहिए। इससे उन्हें पता चलेगा कि ऐसे लक्षणों का शिकार सिर्फ वही नहीं हैं। साथ ही मेडिकल जगत ने जिस तरह की मुस्तैदी कोरोना की वैक्सीन बनाने में दिखाई, वैसी ही तत्परता उसे 'लॉन्ग कोविड' के इलाज में भी दिखानी होगी।

मध्यप्रदेश के स्कूलों में सन्नाटा, फीस वृद्धि का कोलाहल

मध्य प्रदेश में इन दिनों स्कूलों में फीस वसूली को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। स्कूलों के प्रबंधक चाहते हैं कि कोरोना काल के पूर्व की तरह ही छात्र-अभिभावक फीस देते रहें, जबकि अभिभावक सवाल कर रहे हैं कि जब एक साल से स्कूल खुले ही नहीं तो फीस किस बात के लिए दी जाए। इस बीच स्कूलों ने नए सत्र के नाम पर बीस से चालीस फीसद तक फीस बढ़ा दी है।

सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग इस विवाद में कोई स्पष्ट राय नहीं बना पा रहा है। कभी वह स्कूल प्रबंधकों की तरफ लुढ़कता दिखता है तो कभी अभिभावकों वाली बात कह देता है। हाल ही में इसी विषय को लेकर राजधानी भोपाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने शिक्षा विभाग में बनी अनिर्णय की स्थिति को उजागर कर दिया। फीस वृद्धि के प्रस्ताव के विरोध में तर्क दे रहे अभिभावकों के एक समूह को स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने झुंझलाहट में कह दिया कि मैं क्या करूं, मरना हो तो मर जाओ, जो करना हो करो। मंत्री के इस रूखे व्यवहार ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने इसे असंवेदनशील टिप्पणी ठहराया है। अभिभावकों का संगठन भी इस बयान के विरोध में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। फीस वृद्धि को लेकर स्कूल प्रबंधकों एवं अभिभावकों के बीच विवाद को दूर करने के लिए सरकार को जल्द ही कड़े कदम उठाने होंगे। वैसे तो कोरोना काल शुरू होने के साथ ही एक साल से स्कूल-कालेज बंद हैं। छात्रों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। स्कूलों में सन्नाटा बढ़ गया है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी में कमी नहीं आ पाई है। स्कूलों ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपने तरीके से फार्मूला निकाल रखा है। कहीं आधा वेतन मिल रहा है तो कहीं नाम मात्र का। उनकी दलील है कि पूर्व की तरह पूरी फीस नहीं मिल रही है, इसलिए पूरा वेतन नहीं दे पाएंगे। सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग उनकी बातों से लगभग सहमत होते हुए पूरा वेतन देने का दबाव नहीं बना पा रहा है। इसे अनिर्णय की स्थिति ही कहेंगे कि वह एक तरह से दो पाटों में पिस रहा है। एक तरफ अभिभावक हैं जो दलील दे रहे हैं कि कोरोना काल में उनके बच्चे स्कूल नहीं गए और उनके रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया, ऐसे में वे मनमाना फीस क्यों चुकाएं। दूसरी तरफ स्कूलों के प्रबंधक हैं जो तर्क दे रहे हैं कि यदि फीस नहीं बढ़ाई गई तो स्कूल आगे चला पाना मुश्किल है। फीस वृद्धि न करने और केवल ट्यूशन फीस ही लिए जाने की मांग को लेकर अभिभावक काफी दिनों से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्री का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

सुनवाई नहीं हुई तो अभिभावकों का एक समूह राज्यमंत्री के बंगले पर पहुंच गया। उसने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया तो राज्यमंत्री भी तैश में आ गए। फीस बढ़ाने पर आत्मदाह की धमकी दे रहे अभिभावकों से उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूं, मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। इस टिप्पणी ने फीस वृद्धि के विवाद को और गहरा कर दिया है। राज्यमंत्री की झुंझलाहट के दो प्रमुख कारण चर्चा में है। पहला यह कि स्कूल चाहते थे कि एक जुलाई से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएं। इससे शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं खुद राज्यमंत्री भी सहमत थे। उन्होंने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा लेकिन, उन्होंने हरी झंडी नहीं दी। कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को सबसे जरूरी मानते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लौटा दिया। दूसरा कारण यह कि फीस कम नहीं करने को लेकर निजी स्कूल संचालकों का शिक्षा विभाग पर दबाव है। राज्यमंत्री चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले ताकि स्कूलों की व्यवस्था भी चलती रहे। फीस का विवाद नवंबर 2020 में जबलपुर हाई कोर्ट के समझ भी उठा था। तब जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच नवंबर 2020 को कहा था कि स्कूल तब तक छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, जब तक सरकार यह घोषणा नहीं करती है कि कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान किया जाए। जरूरी होने पर उनके वेतन में अधिकतम 20 फीसद की कटौती की जा सकती है। इसके बावजूद स्कूल शिक्षकों व कर्मचारियों को 50 फीसद तक ही वेतन दे रहे हैं।

कम उत्पादन, महंगा बीज और खराब मौसम से सोयाबीन का रकबा आधा, सरसों का होगा दोगुना

किसानों के लिए पीला सोना नहीं रहा अब सोयाबीन

संवाददाता, भोपाल

मप्र कभी सोया राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यहां के किसान सोयाबीन नहीं बोना चाहते हैं। वह कहते हैं कि लगातार घाटे और मौसम की मार से अब सोयाबीन बोना खतरे से खाली नहीं है। पिछले साल उन्होंने सोयाबीन बोया था पर उसमें पौधा अच्छा होने के बाद भी फल नहीं लगे थे, इसका कारण वह अप्रमाणित बीज को मानते हैं। इस साल भी सोयाबीन फसल बोने का समय हो गया है और प्रदेश में बीज का संकट बना हुआ है। यह कहानी केवल मनीष की नहीं है।

मध्यप्रदेश के उन सभी जिलों में जहां सोयाबीन बहुतायत से बोया जाता है, ऐसी ही खबरें आ रही हैं। सोयाबीन का गिरता उत्पादन और पिछले कई सालों से लगातार हो रहा घाटा। वैसे हर साल ही सोयाबीन की फसल में कई तरह की दिक्कतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में बीज का संकट खड़ा हो गया है। मप्र के कई जिलों से प्रमाणित बीज नहीं मिल रहे हैं, किसान बाजार से अप्रमाणिक बीज खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत साढ़े दस हजार रुपए प्रति क्विंटल तक है। उस पर भी अंकुरण की कोई गारंटी नहीं है। सरकार भी मांग के अनुपात में बीज की आपूर्ति नहीं कर पा रही है।

उत्पादन में मप्र अव्वल

मध्यप्रदेश सोयाबीन उगाने के मामले में देश में अव्वल बना हुआ है। रकबे को देखें तो मप्र में देश के कुल सोयाबीन क्षेत्र का 49 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद महाराष्ट्र की 34 प्रतिशत और राजस्थान की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसी तरह उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश की 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बाद महाराष्ट्र की 32 प्रतिशत और राजस्थान की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बावजूद अब किसानों का सोयाबीन से मोहभंग हो रहा है। किसानों की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान देने वाली सोयाबीन पर अब किसानों का भरोसा डगमगाने लगा है। बीते 3 साल से इसका उत्पादन एक तिहाई तक रह गया है। लगातार नुकसान के नतीजे इस खरीफ सीजन में दिखाई दे रहे हैं।

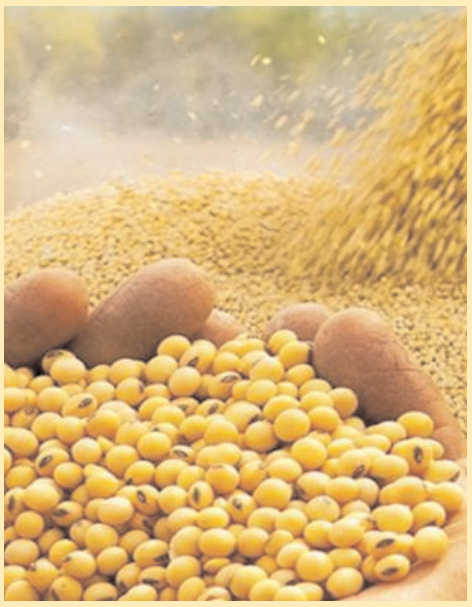

बीज के फेर में फंसा किसान

दरअसल, सालों पहले जब मशीनें से ज्यादा काम नहीं होता था, तब किसान खुद ही सोयाबीन का बीज संरक्षित कर लेता था, लेकिन पिछले एक दशक में मशीनों की उपलब्धता ने ज्यादातर कटाई का काम हारवेस्टर से ही हो रहा है। हारवेस्टर से निकला हुआ दाना बीज बनने लायक नहीं होता है, इससे हर साल बीज खरीदना किसान की मजबूरी है। बीज बनाने का काम दो तीन स्तरों पर किया जा रहा है। इसमें एक हिस्सा सरकारी बीज निगम से पूरा होता है, दूसरा हिस्सा खुले बाजार में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बीज वितरण का काम होता है और तीसरा हिस्सा किसानों द्वारा एक दूसरे को बीज बेचकर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजों के मामले में कई लोचे हैं।

रकबा बढ़ा, उत्पादन घटा

मप्र के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित आंकड़े कि आंकड़े बताते हैं कि पिछले सालों की अपेक्षा सोयाबीन क्षेत्र का रकबा 14 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि इससे उत्पादन नहीं बढ़ा, मप्र में पिछले साल कुल तिलहन फसलों के उत्पादन में 27 प्रतिशत की कमी आई है जबकि सोयाबीन के कुल उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 33.62 प्रतिशत की कमी आई है। इसका एक कारण खराब मौसम भी है। प्रोफेसर कश्मीर सिंह उप्पल कहते हैं कि बेमौसम भारी बारिश या अतिवृष्टि इसमें लगातार घाटा हुआ है और लोग इससे दूर हो रहे हैं। फसल बीमा के आंकड़ों को देखें तो यह बात सही भी लगती है। वर्ष 2020 में जहां रबी फसल में 8.95 लाख किसानों को फसल बीमा मिला, जबकि खरीफ के सीजन में 95 लाख किसानों ने फसल खराब होने का दावा प्रस्तुत कर बीमा लिया है। हालांकि बीमा की राशि नुकसान की तुलना में काफी कम है।

दुग्ध संघ ने दूध के क्रय भाव में किया इजाफा

-किसानों को मिलेगा एक से 2 रुपए प्रति लीटर का फायदा

-आम जनता पर नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का आर्थिक भार

इंदौर। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने दूध के क्रय भाव में वृद्धि कर दी है। इस निर्णय से किसानों को 1 से 2 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा। कुछ समय पहले दुग्ध संघ ने कोरोना संक्रमण के कारण दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध क्रय भाव में कमी की गई थी। जिसे लेकर किसानों में आक्रोश भी था। हालांकि इस बढ़ोतरी से आम जनता को किसी प्रकार से आर्थिक मार नहीं पड़ेगी।

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश कोरोना संक्रमण से उबर रहा है, जिसके कारण पैकेट दूध के विक्रय की मांग में वृद्धि हुई है। इस परिस्थिति में संचालक मंडल की स्वीकृति से दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध क्रय भाव में 20 रुपए प्रति किलो फेट की वृद्धि की गई है। एक जुलाई से भैंस के दूध खरीदी भाव 60 रुपए प्रति किलो फेट एवं गाय के दूध खरीदी भाव 220 रुपए प्रति किलो हो गया है। पटेल का कहना है कि संचालक मंडल का हमेशा प्रयास रहता है कि दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध के अच्छे क्रय भाव दिए जाएं। कोरोना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में दुग्ध चूर्ण एव मक्खन की मांग नहीं होने की मजबूरी से दूध के क्रय भाव कम करने पड़े थे, लेकिन वर्तमान में बाजार की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। इसे देखते हुए आने वाले समय में संचालक मंडल दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध खरीदी भाव में और वृद्धि करने का प्रयास करेगा।

दो महीने पहले कम किए थे भाव

दो महीने पहले दुग्ध संघ ने जो छह रुपए प्रति फैट किसानों को मिलता था, उसमें 20 पैसे प्रति फैट में कटौती कर दी थी। संघ ने किसानों से 5.80 पैसे फैट के हिसाब से दूध लेने का निर्णय लिया था। 17 मई को सांची दुग्ध संघ इंदौर के अध्यक्ष व संचालक मंडल ने दूध के लाभात्मकता बनाए रखने की शर्त के साथ गाय व भैंस के दूध की क्रय दर में कमी को लेकर सहमति मांगी थी। इस पर प्रबंध संचालक भोपाल द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

राजपुरा के एक आम की कीमत दो हजार रुपए

कलेक्टर ने राजपुरा में किसान के बगीचे में जाकर देखे आम

संवाददाता, धार

जिले के राजपुरा के किसानों द्वारा अफगानिस्तान का अमरापुरी और मैक्सीको का पटपल आम पैदा किया जा रहा है। हाल ही में मांगोद-मनावर मार्ग स्थित खेत व बगीचों में गंधवानी जाते समय कलेक्टर आलोक कुमार सिंह पहुंचे। अमरापुरी का ढाई किलो वजनी आम देख कलेक्टर बोले इट इज सो वेरी ब्यूटीफुल। ऐसी नस्ल जिले में मिलना सराहनीय है।

किसान ने बताया अफगानिस्तान की वैरायटी को उप्र से लाकर 10 साल पहले लगाई थी। जो अब फल देने लगी है। राजपुरा के रामेश्वर अगलेचा व जगदीश अगलेचा दोनों भाइयों ने 15 साल पूर्व 35 बीघा के खेत में 2000 आम के पौधे लगाए थे। देश-विदेश की 50 वैरायटी के आम भी शामिल थे। जो फल देने लगे है। किसान अगलेचा ने बताया 50 वैरायटी में मुख्य रूप से फजली इलाहाबाद, चौसा आम हिमाचल प्रदेश, अमृता लखनऊ, केशर जूनागढ़, लगड़ा यूपी, हापुस गुजरात, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत देश के अनेक राज्य और विदेश की वैरायटी है।

भेज रहे गुजराज-महाराष्ट्र

इन्हें गुजरात, महाराष्ट्र भेज रहे हैं। जहां एक आम की कीमत करीब दो हजार है। कलेक्टर ने बगीचे को देख पेड़ पर लगे आम के साथ फोटो लेकर इसका स्वाद भी चखा। मैक्सिको का पटपल आम भी अब उत्पादन देने लगा है। इसका भी स्वाद कलेक्टर ने चखा। इस वैरायटी को किसान ने अहमदाबाद से लाकर 10 साल पहले लगाई थी। एक आम की कीमत पांच सौ रुपए है।

कलेक्टर ने जानकारी लेकर सराहना कर उत्साहवर्धन किया

पाली हाउस में 50 लोगों को रोजगार

यहीं के किसान शोभाराम चौधरी द्वारा पाली हाउस में 30 से 45 दिन में 15 लाख से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने पूछा कितने को रोजगार मिला है, किसान ने बताया 50 से अधिक महिला-पुरुष को रोजगार एक साल से दे रहे हैं। यहां चोटिला गुजरात की गिर गाय को कलेक्टर ने गुड़ खिलाकर काम करने वाली महिलाओं से चर्चा की। जिपं सीईओ आशीष वशिष्ट, एसडीएम बीएस कलेश, सरदापुर सीईओ शैलेंद्र शर्मा, गंधवानी आरईएस एसडीओ वीरल पटेल आदि साथ थे।

बालाघाट की पहचान बनेगा ब्लैक और रेड राईस

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट

धान उत्पादक जिले के नाम से देश में विख्यात है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। बालाघाट जिला अब ब्लैक एवं रेड राईस के उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। बालाघाट अब चित्रौर के साथ ब्लैक एवं रेड राईस के लिए भी पहचाना जाएगा। परसवाड़ा विकासखंड मुख्यालय से 7 किमी दूर पर ग्राम कनई स्थित है। इसी ग्राम के युवा ताराचंद बेलजी ने नानाजी देशमुख चित्रकूट विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर अपने खेत में ब्लैक और रेड राइस का उत्पादन प्रारंभ किया है। ताराचंद बेलजी द्वारा अपने स्वयं के 20 एकड़ खेत में ब्लैक एवं रेड दोनों प्रजाति की धान लगाकर बीज व चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इस सबंध में ताराचंद बेलजी ने बताया कि ब्लैक राइस शुगर (मधुमेह) की बीमारी में बहुत फायदेमंद है। जबकि रेड राइस में विटामिन बी-12 बहुतायत मात्रा में पाया जाता है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में कारगर है। हल्की प्रजाति की यह धान बालाघाट जिले के वातावरण के अनुकूल है। बालाघाट के किसानों ने ब्लैक व रेड राईस की बोवनी कर रहे हैं।

ब्लैक-रेड राइस से बढ़ाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

चित्रकूट विवि की प्रेरणा से जिले में शुरू हुआ उत्पादन

दूसरे राज्यों में भेज रहे बीज

महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उडीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी रेड व ब्लैक राइस धान बीज की मांग बढ़ी है। इन राज्यों के कुछ किसानों को उनके द्वारा डाक के माध्यम से धान का बीज भिजवाया गया है।

समर्थन मूल्य की दरकार

बेलजी ने बताया कि अन्य धान की तरह ही रेड व ब्लैक धान को भी प्राथमिक सहकारी सोसायटी में समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था हो जाए तो इसकी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अधिक आय होगी।

भारतीय समवेत औषधि संस्थान जम्मू के सहयोग से नवाचार

नींबू और गुलाब घास की खेती से चमकेगी किस्मत

नीरज जैन, टीकमगढ़

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ द्वारा भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के सहयोग से जिले में नीबू और गुलाब घास की खेती के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नबम्बर 2020 में कांटी ग्राम में 24 किसानों के यहां एक-एक एकड़ के खेत पर नीबू और गुलाब घास लगवाया गया था। आज इन घासों को प्रथम कटाई करके गांव में लगाए गए तेल निकालने वाले संयंत्र से इसका तेल निकाला गया। जिसका बाजार मूल्य 1000 से 1500 रुपए प्रति लीटर है। एक एकड़ मे लगभग 10-15 लीटर तेल प्राप्त होता है। तेल निकालते समय डॉ. आरके. प्रजापति (वैज्ञानिक), रमाकांत यादव, रावेंद्र (आईआईआईएम जम्मू) मौजूद रहे। गावं के 25 किसान तेल निकलता देख उत्साह से भरे हए थे। डॉ. बीएस किरार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, एसके श्रीवास्तव, उपसंचालक कृषि, सुरेष कुमार कुशवाहा उपसंचालक उद्यानिकी द्वारा मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करके डॉ. आरके प्रजापति इस परियोजना को पूरे जिले में फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बुंदेलखंड में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि यहां की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करती है। यहां की खेती कम बारिश, मिट्टी की कम जलधारण क्षमता, जंगली घरेलू जानवरों के कारण फसल की बड़े पैमाने पर क्षति होती है।

सुगंधित पौधों की खेती उपयुक्त

बुंदेलखंड क्षेत्रों की प्रमुख समस्या छोटे आकार की भूमि जोत और कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में 65 - 85 फीसदी खेती योग्य भूमि वर्षा आधारित एवं बंजर अनुउपजाऊ के क्षेत्र है। नियमित कृषि फसलें, अनाज, दालें आदि पानी की कमी के कारण संतोषजनक उपज नहीं दे पातीं। दूसरी तरफसीमित कृषि क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता।

इनका कहना है

किसानों की आय बढ़ाने और राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मांग कृषि में नीबू और गुलाब घास के तेल की बढ़ने से एवं जोखिम को पूरा करने के लिए मौजूदा कृषि प्रणाली में औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती उपयुक्त है।

- डॉ. आरके प्रजापति,
वैज्ञानिक, कृषि केंद्र टीकमगढ़

इन फसलों को मुख्य फसल के साथ अथवा बंजर भूमि, कम सिंचित क्षेत्र, शुष्क भूमि और वर्षा आधारित क्षेत्रों पर की जा सकती है।

- डॉ. बीएस किरार,
वैज्ञानिक, कृषि केंद्र टीकमगढ़

सुगंधित फसलों की खेती बुंदेलखंड के किसानों की आय और कृषि उत्पादन के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। इसकी खेती से हमारे किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उनकी आय भी बढ़ेगी।

एसके श्रीवास्तव,
उपसंचालक कृषि, टीकमगढ़

सुगंधित फसलों की खेती जिले में शुरू होने से सुगंधित तेल के प्रसंस्करण और मूल्यसंवर्धन उद्योग तथा उद्यामिता विकास का जिले में आकर्षित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- एसके. कुशवाहा,
उपसंचालक उद्यानिकी, टीकमगढ़

सुगंधित फसलों में अधिक खाद उर्वरक, सिंचाई आदि लागत की जरूरत नहीं रहती। जानवर भी इन फसलों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इससे किसानों की आय में इजाफा ही होगा।

- डॉ. आईडी सिंह,
कृषि वैज्ञानिक

70 फीसदी फसलों में रुका अंकुरण, 30 प्रतिशत पर संकट | जिन किसानों के पास सिंचाई का साधन नहीं वे बदहाल | विदिशा में कई जगह दोबारा बोवनी तक की आई नौबत | खरीफ फसल का कुल रकबा 5 लाख 32 हजार हेक्टेयर

पहले बरसे, अब तरसे!

बारिश रुकने से सूखने लगी जमीन

संवाददाता, विदिशा

जिले में बारिश का दौर थम गया है। जमीन सूखने लगी है। मिट्टी की पपड़ी बनकर ऊपर आ गई है। काली मिट्टी के अंदर नमी 5 सेमी से नीचे पहुंच गई है। ऐसे में 30 फीसदी खरीफ फसलों की बोवनी पर संकट के बादल छा गए हैं। किसानों ने असमंजस में आकर बोवनी रोक दी है। 70 फीसदी किसानों ने पहले से बोवनी कर दी थी। लेकिन उनके खेतों में बीजों के अंकुरण की समस्या आ रही है। ज्वार और मक्के में कई किसानों में दोबारा बोवनी करनी पड़ी। खाईखेड़ा के किसान गणेशराम दुबे और महेश दुबे बताते हैं कि 30 बीघा जमीन में ज्वार बोई थी। एक भी दाना नहीं उगा तो दोबारा बोवनी करनी पड़ी। इसी प्रकार सोयाबीन में भी जो बोवनी हो चुकी है, उसमें नमी की कमी से ठीक से अंकुरण नहीं हो रहा है। लगातार घाटे में जा रही सोयाबीन की फसल का रकबा एक साल में ही दो लाख 55 हजार 200 हेक्टेयर कम हो गया है। यदि बारिश अच्छी होती है तो आने वाले समय में यह रकबा और भी कम होने की संभावना है।

पानी के इंतजार में सूखे धान के गड्ढे

विदिशा-सागर रोड पर मिर्जापुर से लेकर कुआं खेड़ी तक हाइवे के दोनों किनारों पर किसानों ने इस साल बड़ी उम्मीद के साथ 500 हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की रोपाई के लिए गड्ढे बनाए हैं। इनमें पानी भरकर धान की रोपणी लगाने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बारिश की लंबी खेंच के कारण धान के गड्ढे भी सूखे पड़े हैं। इसी प्रकार विदिशा से सांची रोड पर रंगई गांव से लेकर सांची के बीच हाइवे और रेलवे लाइन के बीच में 4000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की बोवनी होती है। यहां किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं। इसलिए बारिश की कमी के बाद भी किसानों ने ट्यूबवेल से पानी भरने की तैयारी कर ली है।

दोबारा बोवनी की नौबत

अधिकांश किसानों का कहना है कि मक्का, ज्वार और धान की फसलों में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। पानी की कमी से उक्त सभी फसलें जल्दी सूखने लगती हैं। इस साल इन फसलों में दोबारा बोवनी की जरूरत पड़ रही है। सिंचाई के साधन भी नहीं हैं।

21 जून को की थी धान की बोवनी

विदिशा-अशोकनगर रोड पर कोठीचारकला गांव के किसान प्रमेंद्र रघुवंशी और रामबाबू रघुवंशी बताते हैं कि 21 जून को 30 बीघा रकबे में सीड ड्रिल पद्धति से धान की बोवनी की थी। 30 जून तक 10 दिन बाद भी पौधों का अंकुरण नहीं हुआ है। हमारे पास सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का साधन नहीं है। इस कारण फसलों की सिंचाई अलग से नहीं कर पा रहे हैं। इस गांव में 20 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो बोवनी तो कर चुके हैं लेकिन उनके खेतों में पौधों का अंकुरण नहीं हो रहा है। गांव के ही शंभू सिंह का कहना है कि उनकी सोयाबीन फसल पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। पौधे ठीक से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बीज का जर्मिनेशन प्रभावित हो रहा है।

इनका कहना है

खरीफ फसलों को पानी की तुरंत जरूरत है। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं। अब जमीन भी फटने लगी है। काली मिट्टी में अगले 5 दिनों तक थोड़ी नमी तो रहेगी, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई तो फसलों पर असर पड़ेगा। जिले में 70 फीसदी बोवनी पूरी हो चुकी है। 30 प्रतिशत बोवनी अभी बाकी है। अभी तक फसलों के नुकसान की जानकारी नहीं है।

-एनपी प्रजापति,
सहायक संचालक कृषि विभाग, विदिशा

‘मां की बगिया’ से होगा कुपोषण का खात्मा

- सशक्त होंगे स्व-सहायता समूह और आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं
- मां की बगिया से जुड़ेगा एमडीएम, मनरेगा अभिशरण से होगी मदद
- कुपोषण के खात्मे के साथ विद्यार्थियों को मिलेगा बागवानी का प्रशिक्षण
- पोषण वाटिका होंगे मां की बगिया में परिवर्तित, कराहल से हुई शुरुआत

संवाददाता, श्योपुर

गांव-गांव में समूह बनाकर स्कूल और आंगनबाड़ियों पर एमडीएम देने का काम कर रही स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार ने एमडीएम चलाने वाले स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए मां की बगिया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्योपुर जिले में कराहल विकासखंड के रानीपुरा माफी गांव से जिला पंचायत सीईओ राजेश शुक्ल ने की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर सरकारी स्कूलों में मां की बगिया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत स्कूलों की पोषण वाटिका को विकसित कर उसे मां की बगिया का स्वरूप दिया जाएगा। प्रदेशभर के स्कूलों में 7100 पोषण वाटिका संचालित हैं, जिन्हें अब मां की बगिया के नाम से पुकारा जाएगा। यह कार्यक्रम सिर्फ नामकरण परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि कुपोषण के खात्मे के लिए भी मील के पत्थर साबित होगी। इस काम में पैसे की कमी न हो इसलिए एमडीएम से जुड़ी इस योजना को मनरेगा अभिशरण से भी जोड़ा गया है।

पांच-पांच हजार खर्च करने के निर्देश

जिले में इसका शुभारंभ जिपं सीईओ शुक्ल ने करते हुए योजना में पैसे की किसी तरह कमी न हो इसलिए पंचायतों को मनरेगा अभिशरण से प्रत्येक शाला में मां की बगिया के लिए 5-5 हजार रुपए खर्च करने के निर्देश दिए हैं। कराहल विकासखंड में इस कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी सेवा आश्रम के माध्यम से की जा रही है।

अब विद्यार्थी सिखेंगे खेती के गुर

मां की बगिया कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के माध्यम से स्कूलों में ही वह सब्जियां उगाई जाएंगी। इन सब्जियों में अधिकतर वो होंगी जो एमडीएम पकाने में उपयोगी हो। स्व सहायता समूह की महिलाएं सब्जी उगाने का काम खुद करेंगी। इस काम में विद्यार्थियों की मदद शैक्षणिक दृष्टि से ली जा सकेगी ताकि, वह बागवानी का काम पाठशाला में ही सीख सके।

तीन हजार कुपोषितों को न्यूट्रीमिक्स का होगा वितरण

मां की बगिया का शुभारंभ करने रानीपुरामाफी पहुंचे जिपं सीईओ ने बताया कि, बीएमजेड तथा डब्ल्यूएचएच के सहयोग से महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित पोषण समृद्ध कार्यक्रम के तहत कराहल विकासखंड में 3 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए न्यूट्रीमिक्स का वितरण किया जाएगा एवं गर्भवति माताओं को दाल-दलिया, सरसों का तेल उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि, गांधी सेवा आश्रम जनसेवा के माध्यम से काम कर रहा है और आमजन भी उन पर विश्वास करते हैं इसलिए मां की बगिया कार्यक्रम को भी उनके माध्यम से समूह द्वारा संचालित कराएंगे। यही नहीं, स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव-गांव में वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप आदि का निर्माण कराया जाएगा।

पटवारी लामबंद

- लंबित मांगों को लेकर खोला मोर्चा
- राजस्व कार्यों का भी करेंगे बहिष्कार

संवाददाता, भोपाल

एक बार फिर पटवारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि चरणबद्ध आंदोलन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पहले काला मास्क पहनकर विरोध जताएंगे और बाद में कार्यों का बहिष्कार करेंगे। पटवारी संघने 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। मप्र पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का फैसला कर लिया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया राजस्व विभाग सहित करीब 56 विभागों में अपनी सेवा देने वाले पटवारी कई सुविधाओं से मोहताज हैं। पटवारियों की अनेक मांगें हैं लेकिन तीन प्रमुख हैं। इनमें पटवारियों का ग्रेड पे 2800 करते हुए समय मान वेतनमान विसंगतियों को दूर किया जाए। पटवारियों को गृह जिले या गृह जिले के आसपास पदस्थापना दी जाए। नए पटवारियों की सीपीसीटी नियम की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

एप करेंगे अनस्टाल

पटवारियों की मांगों को लेकर अलग-अलग चरण में आंदोलन जारी रहेगा। सात जुलाई को सभी पटवारी अपने मोबाइल से सभी शासकीय ऐप अनस्टाल करेंगे।

आंदोलन में कब-क्या

- 7 से 9 जुलाई तक काली पट्टी और काला मास्क लगाकर काम करेंगे।
- 12 जुलाई को भू-अभिलेख विभाग को छोड़कर अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार।
- 2 से 4 अगस्त तक सभी पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
- 3 अगस्त को जिला स्तर पर पटवारियों की रैली का आयोजन होगा।
- 5 अगस्त को वेब पोर्टल, वेबजीआइएस सहित सभी आनलाइन कार्यों का बहिष्कार।
- इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो 10 अगस्त सेअनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

अब आयोग ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी

भोपाल। मप्र राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के पहले सभी उम्मीदवारों की सूची, शपथ पत्र और जीतने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगी। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आगामी पंचायत चुनाव में इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौर में पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सूचना के लिए भीड़ नहीं लगना चाहिए। इसकी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होना चाहिए। मध्यप्रदेश चुनाव आयोग राजपत्र में हर पंचायत चुनाव में निर्देश जारी करता है। इसमें उम्मीदवारों की जानकारी, शपथ पत्र, क्रिमिनल रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। छोटे राज्य उड़ीसा, बिहार, झारखंड में भी जानकारी उपलब्ध है। सिंह ने टिप्पणी में कहा कि जब दूसरे राज्य जानकारी उपलब्ध करा सकते है, तो मध्यप्रदेश चुनाव आयोग क्यों नहीं करता है।

आयोग की वेबसाइट पर डालना होगा उम्मीदवारों का शपथ-पत्र

ग्राम पंचायतों में निस्तार, सिंचाई व पेयजल का तैयार किया जाएगा आंकड़ा

ग्राम पंचायतों का बनाया जा रहा जल बजट

संवाददाता, भोपाल

ग्राम पंचायतों में निस्तार, सिंचाई व पेयजल के लिए कितने जल की आवश्यकता है। वर्तमान जल संरचनाओं से कितने जल की आपूर्ति हो रही है। भविष्य में कितने जल की आवश्यकता होगी व वर्षा जल के संचयन से कितना जल किन-किन संरचनाओं से संधारित किया जा सकता है। इन सभी आंकड़ों की गणना के आधार पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत का जल बजट तैयार किया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह बजट सहायक यंत्री व उपयंत्रियों के मार्गदर्शन में बनाया जाए। ग्राम पंचायतों के सभी आंकड़े परिक्षण उपरांत ही प्रविष्ट किए जाएं, जिससे सही बजट तैयार हो सके।

आनलाईन प्रशिक्षण

बजट मनरेगा योजना अंतर्गत तैयार किया जा रहा है व इसके संबंध में जिले के समस्त सहायक यंत्री व उपयंत्रियों को राज्य स्तर से आनलाईन प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। प्रशिक्षण में ग्राम रोजगार सहायकों की उपस्थिति तय की गई है। बजट के लिए राज्य स्तर से प्रपत्र निर्धारित किया गया है। सांख्यकीय आंकड़ों पर आधारित इन प्रपत्रों में ग्राम पंचायतें की जनसंख्या, पशुसंख्या, वनक्षेत्र, राजस्व रकबे, कृषि भूमि, मौजूदा जल संरचनाओं, विभिन्ना फसलों के उत्पादन की विस्तृत जानकारी ग्राम रोजगार सहायकों व उपयंत्रियों को प्रविष्ट करनी होती है। जिसके उपरांत ग्राम पंचायत में वर्षा जल के बहाव की गणना के आधार पर यह निर्धारित होता है कि किस पंचायत में कितनी व कौनसी जल संरचनाएं निर्मित की जाना आवश्यक है जिससे पेयजल निस्तार व सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त पूर्ति हो सके व भविष्य में भू जल स्तर को भी सुधारा जा सके।

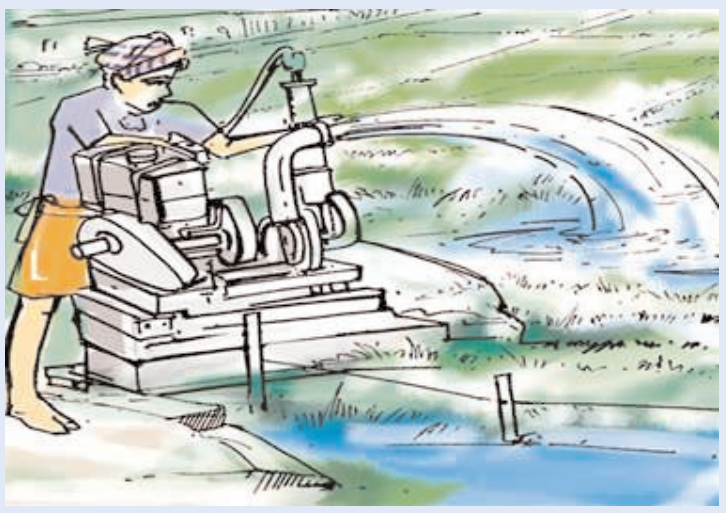

सीईओ को निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में वाटर बजट तैयार किए जाने के लिए जनपद स्तरीय बैठकों में भी जिले से विस्तृत निर्देश व मार्गदर्शन प्रदाय किया जा चुका है। जिससे सही तरीके से वाटर बजट बनाया जा सके। साथ ही उक्त कार्य को प्राथमिकता से व समय सीमा में किए जाने के निर्देश भी सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व सहायक यंत्रियों को दिए गए हैं।

ग्वालियर को मिली राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय की सौगात

केंद्रीय मंत्री तोमर और मध्यप्रदेश के मंत्रियों के आतिथ्य में हुआ श्रीगणेश

चंबल में मुरैना के किसानों के लिए वरदान साबित होगा 'हनी मिशन'

अवधेश डंडोतिया, ग्वालियर/मुरैना

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर-चंबल अंचल के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इसके जरिए बागवानी के लिए बड़ी आर्थिक मदद और प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे किसानों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा और उनके लिए प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर कही। तोमर ने कहा कि इन सुविधाओं के साथ ही भविष्य में भी सरकार की ओर से हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस प्रकार से सरसों के कारण चंबल क्षेत्र पूरे देश में जाना जाता है, उसी प्रकार से शहद उत्पादन में अग्रणी मुरैना जिले सहित चंबल क्षेत्र देशभर में जल्द ही हनी हब के रूप में प्रसिद्धि पाएगा।

ये हनी मिशन मुरैना क्षेत्र के गरीब किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव लाएगा और इससे उनकी आय बढ़ेगी। शहद उत्पादन में मप्र में मुरैना अग्रणी है। यहां लगभग छह हजार मधुमक्खी पालक व एक लाख मधुमक्खियों के बक्सों की संख्या है, जिससे तीन हजार टन शहद उत्पादन होता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी, मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। ग्वालियर व्यापार मेले के सामने कृषि परिसर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के इस क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है।

मप्र के 21 जिलों को होगा फायदा

नया केंद्र ग्वालियर में खुलने से न केवल ग्वालियर संभाग के किसान, बल्कि उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसान योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इस केंद्र से जिन 21 जिलों को कवर किया जाएगा, उनमें चंबल, ग्वालियर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिले शामिल हैं। ये जिले हैं- ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, अशोक नगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवारी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया।

यह रहे मौजूद

कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह, प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी किशोर कान्याल भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल भी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

मप्र में अब दो कार्यालय

उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के बाद मध्यप्रदेश अब ऐसा राज्य बन गया है जहां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के दो कार्यालय हो गए हैं। ग्वालियर से पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल में बागवानी बोर्ड का कार्यालय संचालित था। प्रदेश सरकार की मांग पर केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर ने ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों को यह सौगात दी है। इस कार्यालय की स्थापना के लिए प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह विशेष रूप से प्रयासरत थे।

किसानों को फायदा

गौरतलब है कि जहां-जहां पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय हैं उस क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा मिला है। इस कार्यालय के जरिए अनुदान व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर किसानों ने बड़ी आमदनी अर्जित की है। बागवानी बोर्ड के कार्यालय के माध्यम से उद्यानिकी फसलों मसलन फल, सब्जी, कोल्ड स्टोरेज चैन, ग्रीन हाउस, नेट हाउस व मलचिंग खेती के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है।

बनाएंगे शहद का हब

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि परंपरागत फसलों से किसानों की आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को हर्बल व फलों जैसी नगदी खेती अपनानी होगी। बागवानी फसलों के लिए केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ग्वालियर एवं चंबल अंचल के किसानों की समृद्धि के लिए इस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी सौगातें दी गई हैं, जिसमें भारत और इजराइल के सहयोग से नूराबाद में निर्माणाधीन एक्सीलेंस सेंटर, ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, मुरैना को शहद का हब बनाने के लिए अत्याधुनिक लैब और ग्वालियर में आलू के वृहद उत्पादन के लिए प्रस्तावित टिश्यू कल्चर लैब शामिल है।

बिना गारंटी मिलेगा ऋण

तोमर ने यह भी कहा कि सरकार ने एक लाख करोड़ का कृषि अधोसंरचना कोष बनाया है। जिससे मदद लेने के लिए कोई भी किसान अपना प्रोजेक्ट बनाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन प्राप्त होने वाले किसानों के प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार द्वारा हर हफ्ते समीक्षा की जाती है। भारत सरकार एफपीओ (कृषि उत्पादन संगठन) के जरिए 6 हजार 550 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। एफपीओ के जरिए कृषकगण 300 किसानों का समूह बनाकर दो करोड़ रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के और सस्ती दर पर प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है।

आत्म निर्भर होंगे किसान

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल के किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। बागवानी बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। इससे किसान सब्जी, फूल, कोल्ड स्टोर, चैन इत्यादि के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही फूड प्रोसेसिंग इकाइयां भी स्थापित की जा सकेंगी।

अब 450 रुपए में गाय देगी अच्छी नस्ल की बछिया

- अब जिले के पशुपालकों को मिलेगी बछिया पैदा करने वाली तकनीक
- श्योपुर के पशु पालन विभाग ने मंगवाए सेक्स्ड सीमन के 250 डोज
- नजदीकी पशु अस्पतालों से पशु पालकों को उपलब्ध हो सकेंगे डोज

संवाददाता, श्योपुर

जिले के पशुपालकों को अब 450 रुपए में ऐसी तकनीक मिलेगी, जिसके इस्तेमाल से गाय बछिया को ही जन्म देगी। इस नई तकनीक से पैदा होने वाली बछिया नस्ल भी अच्छी होगी, जो गाय बनने पर दूध भी अच्छा देगी। श्योपुर जिले के पशुपालन विभाग ने इस नई तकनीक (सेक्स्ड सीमन) के 250 डोज मंगवा लिए हैं। पशुपालन विभाग के अफसरों का कहना है कि जिले के पशुपालकों को सेक्स्ड सीमन के डोज नजदीक के पशु अस्पतालों से शुल्क जमा करने के बाद उपलब्ध हो जाएंगे। गौरतलब है कि घटती जमीन और बढ़ते मशीनीकरण के कारण बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई है, जो दुधारू पशु हैं उन्हीं का पालन-पोषण होता है। इसलिए लोग अब अनुपयोगी हो चुके बछड़ों को ऐसे ही आवारा छोड़ देते हैं, जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। आवारा घूमने वाले ये बछड़े जहां सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। वहीं फसलों को चौपट भी कर देते हैं। जिले के कई गांवों के लोग इन आवारा मवेशियों के कारण परेशान हैं। क्योंकि वे उनकी फसल को चौपट कर रहे हैं। लेकिन अब बछड़ों की बढ़ती संख्या शासन की सेक्स्ड सीमन योजना के तहत नियंत्रित हो जाएगी। बताया गया है कि सेक्स्ड सीमन के इस्तेमाल के बाद गाय से बछड़ा नहीं, बल्कि बछिया ही पैदा होगी। भैसों के लिए भी सेक्स्ड सीमन उपलब्ध है। जिसके इस्तमाल से भैस भी पड़िया को जन्म देगी।

पहले 2 हजार थी कीमत

पशु विभाग ने इस नई तकनीक के 250 डोज मंगवा लिए हैं। जिले का जो पशुपालक इस फॉर्मूले का लाभ लेना चाहेगा, उसे इसका खर्चा स्वयं ही उठाना पड़ेगा। उप संचालक पशु डॉ. राजेश सिकरवार ने बताया कि पहले सीमन के डोज की कीमत करीब 2 हजार रुपए थी, लेकिन अब इस डोज की कीमत घटाकर 450 रुपए हो गई है।

पशु चिकित्सक घर जाकर करेंगे सीमन

पशु चिकित्सा विभाग के अफसर बताते हैं कि पशुपालक को गाय के हीट पर आने की सूचना 24 घंटे के अंदर नजदीकी पशु चिकित्सालय में देनी होगी। इस सूचना के बाद पशु चिकित्सक संबंधित पशुपालक के घर जाकर गर्म गाय का सीमन करेंगे। इस सीमन के बाद गाय अच्छी नस्ल की बछिया को जन्म देगी।

इनका कहना है

सेक्स्ड सीमन के प्रयोग से सौ प्रतिशत गारंटी के साथ गाय बछिया को ही जन्म देगी। पशुपालकों के लिए हमने सेक्स्ड सीमन के 250 डोज मंगा लिए हैं। एक डोज का खर्चा 450 रुपए संबंधित पशुपालक को उठाना होगा।

- डॉ. राजेश सिकरवार, उप संचालक, पशु विभाग, श्योपुर

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लौरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)